MOST IMMEDIATE
IMPORTANT

No. 17013/20/2024-PR
Government of India
Ministry of Home Affairs
***

Women Safety Division, 2nd Floor
Major Dhyan Chand National Stadium
India Gate, New Delhi-110001
October 24, 2024

To

1. **The Chief Secretaries of all States and UTs**
2. **DG/IG Prisons and Correctional Services of all States and UTs**

Sub: Special Campaign for implementation of the provisions of section 479 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) by State Prison authorities for providing relief to undertrial prisoners as part of celebrating Samvidhan Divas on 26th November, 2024.

Sir/Madam,

As you are aware, the Ministry of Home Affairs has been taking various steps for addressing the issue of undertrial prisoners in the jails and decongestion of prisons. In this connection, Section 479 of BNSS, inter-alia, provides that "Where a person has, during the period of investigation, inquiry or trial under this Sanhita of an offence under any law (not being an offence for which the punishment of death or life imprisonment has been specified as one of the punishments under that law) undergone detention for a period extending up to one-half of the maximum period of imprisonment specified for that offence under that law, he shall be released by the Court on bail:

Provided that where such person is a first-time offender (who has never been convicted of any offence in the past) he shall be released on bond by the Court, if he has undergone detention for the period extending up to one-third of the maximum period of imprisonment specified for such offence under that law."

2. The Hon'ble Supreme Court, in its Order dated 23rd August, 2024 has also taken cognizance of the above provisions of BNSS and have directed the Superintendents of Jails across the country that wherever accused persons are detained as undertrials, their applications may be preferred to the concerned Courts, upon completion of one-half/one-third of the period mentioned in sub section (1) of section 479 of BNSS, for their release on bail/bond. The Hon'ble Court had also clarified that the provisions of Section 479 of BNSS **'shall apply to all undertrials in pending cases irrespective of whether the case was registered against them before 1st July 2024'**. In this regard this Ministry's Advisory of even number dated 16th October, 2024 may be referred to.

3. The '*Constitution Day*' known as *'Samvidhan Divas'*, is celebrated every year on 26th November to commemorate the adoption of the Constitution of India and for promoting constitutional values among the citizens. As part of the celebrations, it is

proposed to launch a special campaign on 'Samvidhan Divas' wherein all States and UTs, taking advantage of the provisions of Section 479 of the BNSS, will provide relief to undertrial prisoners by following due process. All States and UTs are, therefore, requested to take proactive steps to identify eligible undertrial prisoners and move the Court for their release on bail/bond on 26th November, 2024. States/UTs are also requested to intimate the number of prisoners identified and whose applications have been made in writing to the Court for the release of such persons on bail, in the attached proforma, to MHA

4. It may be noted that Section 479 of BNSS clearly makes an exception for persons who are not eligible for this benefit under the law, namely any offence for which the punishment of death or life imprisonment has been specified as one of the punishments. States/UTs may, therefore, carefully examine all cases while making an application under this Section and exclude the cases of heinous and serious crimes like rape, murder, terrorist acts, POCSO, NDPS, etc., where the punishment of death or life imprisonment has been specified as one of the punishments.

Yours sincerely,

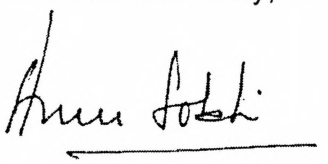

(Arun Sobti)
Director (Prison Reforms)
Tele: 2307 5297
Email: dspr.atc@mha.gov.in

PROFORMA

Name of State/UT: _____

Item	Numbers from 1.7.2024 to 30.9.2024	Numbers from 1.10.2024 to 31.10.2024	Numbers from 1.11.2024 to 26.11.2024
First Time Undertrial Prisoners			
No. of first time UTPs who have served 1/3rd of the maximum sentence prescribed for the offence			
No. of applications preferred in the Court by Jail Superintendent			
No. of UTPs released on bond			
Other Undertrial Prisoners (UTPs)			
No. of UTPs who have completed ½ of the maximum sentence prescribed for the offence			
No. of applications preferred in the Court by Jail Superintendent			
No. of UTPs released on bail			

अति तत्काल
महत्वपूर्ण

सं. 17013/20/2024-पीआर
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
***

महिला सुरक्षा प्रभाग, दूसरी मंजिल
मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम
इंडिया गेट, नई दिल्ली-110001
अक्तूबर 24, 2024

सेवा में

1. **सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव**
2. **सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजी/आईजी जेल**

विषय: 26 नवंबर, 2024 को संविधान दिवस मनाने के भाग के रूप में विचाराधीन कैदियों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य जेल अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 479 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए विशेष अभियान।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप जानते हैं, गृह मंत्रालय जेलों में विचाराधीन कैदियों को राहत प्रदान करने एवं जेलों में भीड़ को कम करने की दिशा में विभिन्न कदम उठाता रहता है। इसी सिलसिले में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 479, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करती है कि "अगर कोई व्यक्ति कानून के तहत किसी अपराध (ऐसा अपराध न हो जिसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा उस कानून के तहत दंडों में से एक के रूप में निर्दिष्ट की गई हो) की जांच, पूछताछ या परीक्षण की अवधि के दौरान उस कानून के तहत उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि के लिए हिरासत में रहा हो, तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

बशर्ते कि जहां किसी ऐसे व्यक्ति ने पहली बार अपराध किया है (जिसे पहले कभी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है) अगर उसने उस कानून के तहत ऐसे अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के एक तिहाई तक की अवधि पूरी कर ली है तो उसे अदालत द्वारा बांड पर रिहा किया जाएगा"

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 23 अगस्त, 2024 के अपने आदेश में बीएनएसएस के उपरोक्त प्रावधानों का संज्ञान लिया तथा देश भर के जेल अधीक्षकों को निर्देश दिया

कि जहां भी आरोपी व्यक्ति विचाराधीन कैदी के रूप में निरुद्ध हैं, वहां उनकी जमानत/बांड पर रिहाई के लिए बीएनएसएस की धारा 479 की उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि का आधा/एक तिहाई पूरा होने पर उनके आवेदन संबंधित न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाएं। माननीय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि बीएनएसएस की धारा 479 के प्रावधान सभी लंबित मामलों में विचाराधीन कैदियों पर लागू होंगे, भले ही उनके खिलाफ मामला 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज किया गया हो। इस संबंध में मंत्रालय की 16 अक्तूबर, 2024 की समसंख्यक एडवाइजरी का संदर्भ लिया जा सकता है।

3. हर वर्ष २६ नवंबर को 'कॉन्स्टिट्यूशन डे' यानी संविधान दिवस के रूप में, भारतीय संविधान को अपनाने एवं देश के नागरिकों के बीच संविधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए उत्सव के रूप में मनाया जाता है। **अतः, 'संविधान दिवस' पर एक विशेष अभियान शुरू करने का प्रस्ताव है,** जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, बीएनएसएस की धारा 479 के प्रावधानों का लाभ उठाते हुए, उचित प्रक्रिया का पालन करके, विचाराधीन कैदियों को राहत प्रदान करें। इसलिए, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि वे पात्र विचाराधीन कैदियों को चिन्हित करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं और जमानत/बांड पर उनकी रिहाई के लिए न्यायालय में याचिका दायर करें। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे ऐसे चिन्हित कैदियों और उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए न्यायालय में लिखित रूप से आवेदन करने की संख्या, संलग्न प्रोफॉर्मा में, गृह मंत्रालय को सूचित करें।

4. यह ध्यान देने योग्य होगा कि बीएनएसएस की धारा 479 का लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति पात्र नहीं होंगे जिनके द्वारा किए गए अपराधों में मृत्यु या आजीवन कारावास को दंडों में से एक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इसलिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस धारा के तहत आवेदन करते समय ऐसे सभी मामलों की बारीकी से जांच करें और बलात्कार, हत्या, आतंकवादी कृत्य, पोक्सो, एनडीपीएस आदि जैसे जघन्य और गंभीर अपराधों के मामलों, जहां मृत्यु या आजीवन कारावास को दंडों में से एक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, उन्हें जमानत की सिफारिश की सूची में शामिल न करें।

भवदीय,

(अरुण सोबती)
निदेशक (जेल सुधार)
टेलीफोन: 2307 5297
ईमेल: dspr.atc@mha.gov.in